समन्वय भवन में राज्य स्तरीय सहकारी कार्यशाला-

पारदर्शिता, ईमानदारी और नवाचार से मजबूत होगा सहकारी आंदोलनः मंत्री

अधीनस्थ पैक्स तक संभागीय और जिला अधिकारी करें दौरा

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि पारदर्शिता, ईमानदारी और नवाचार के जरिए सहकारी आंदोलन को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए पूरी सहकारिता की टीम कृत-संकल्पित होकर काम करें। मंत्री सारंग बुधवार को समन्वय भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न पहलुओं पर राज्य स्तरीय सहकारी कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री सारंग ने कहा कि सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए पैक्स का सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक है। इसके लिए संभागीय और जिला अधिकारी अधीनस्थ पैक्स का निरीक्षण करें। मुख्यालय के अधिकारियों को भी संभागवार जिम्मेदारी दी जाए, जो उनके अधीनस्थों की समस्या एवं सुझावों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने में पैक्स की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मंत्री सारंग ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सहकारिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि केडिट मूवमेंट के साथ सहकारिता के विभिन्न आयामों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता का क्लेवर बदल रहा है। सहकारी आंदोलन को पुनः मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है।

मंत्री सारंग ने बताया कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता के माध्यम से ही गरीबों के घर में खुशी लायी जा सकती हैं। सहकारिता ही ऐसा नेटवर्क है, जिसके माध्यम से हर घर में रोजगार के नए अवसर पैदा किये जा सकते हैं। सहकारिता की साख के लिए काम करें। लोगों को अच्छे कामों के लिए याद रखा जाता है। ईमानदारी से किया गया कार्य आत्मसंतुष्टि देता है, इसलिए जॉब सेटिस्फेक्शन जरूरी है। मंत्री सारंग ने कहा कि हाल ही में केन्द्र सरकार को दिए गए प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन मध्यप्रदेश का रहा। इसके लिए उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी।

अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णबाल ने कहा कि हर पैक्स को केडिट के अलावा तीन एक्टीविटी करना जरूरी है। स्थानीय पृष्ठभूमि में अवसरों को तलाश कर बिजनेस बढ़ाना होगा। संभागीय और जिला अधिकारी को एक-एक पैक्स की समयबद्ध तरीके से समीक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि पैक्स सुदृढ़ हो यह लक्ष्य होना चाहिये। बिजनेस सोसायटियों के सदस्यों के खाते हमारे यहां होना चाहिये। साथ ही उनके लिये माइक्रो एटीएम की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक मनोज पुष्प ने कहा कि सहाकारिता के सकारात्मक बदलाव के दौर में अधिकारी अपनी अहम भूमिका को पहचानकर दायित्वों का निर्वहन करें। सहकारिता के मॉडलाइजेशन को धरातल पर क्रियान्वित करें। अधिकारी अपनी लीडरशिप में प्रगति का फॉलोअप लें और पैक्स को बिजनेस यूनिट बनाने में सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की नवाचार विंग और सीपीपीपी मॉडल को भूरी-भूरी प्रशंसा मिली है। यही नहीं कंप्यूटराइजेशन की दिशा में भी मध्यप्रदेश देश में नंबर एक पर रहा है, जो सराहनीय है। मंत्री सारंग ने कहा कि कमिटमेंट दक्षता को सिद्ध करता है। सभी टीमवर्क के साथ काम करें। यूनिफार्मलिटी जरूरी है। साफ सुथरा ईमानदारी से किया गया कार्य ही आपकी पहचान बनेगा जिससे आपका नाम होगा। जॉब के लिए ईमानदार रहेंगे, तो सफल होंगे। मंत्री सारंग ने शुरूआत में संभाग और जिलों के आए अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और बिना बताए अनुपस्थित अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री लुधियाना में 7 को उद्योगपतियों से करेंगे संवाद

बैंगलुरु और सूरत के बाद अब लुधियाना के उद्योगपति 'एडवांटेज एमपी' यानि निवेश के सुअवसरों से रूबरू होंगे डॉ. सीएम यादव

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मध्यप्रदेश में निवेश के नए द्वार खोलने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में चल रही औद्योगिक संवाद श्रृंखला में प्रमुख इंटरएक्टिव सेशन लुधियाना में 7 जुलाई 2025 को होने जा रहा है। बैंगलुरु और सूरत में निवेशकों से मिले सकारात्मक प्रतिसाद के बाद अब लुधियाना में तीसरा इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपोर्चूनिटीज इन मध्यप्रदेश आयोजित होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव लुधियाना के प्रमुख उद्योगपतियों, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के निवेशकों के साथ सीधे संवाद करेंगे। यह आयोजन केवल विचारों के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें संभावित निवेश प्रस्तावों पर ठोस चर्चा भी की जाएगी। मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीति, सेक्टर-फोकस्ड रणनीतियां और ग्राउंड-रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इस संवाद का केंद्रीय आकर्षण होंगे। लुधियाना की पहचान भारत के विनिर्माण हब के रूप में रही है, विशेष रूप से वस्त्र और मशीनरी निर्माण में लुधियाना की विशेष पहचान है। ऐसे में इस क्षेत्र के उद्यमियों का ध्यान मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं की ओर आकृष्ट करने के लिए यह सेशन महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव राज्य की विशेष औद्योगिक परियोजनाओं – जैसे एमपी टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्रा पार्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर विस्तार से जानकारी देंगे। बैंगलुरु में आईटी और इनोवेशन से जुड़े निवेशकों के साथ संवाद और सूरत में टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री के उद्योगपतियों से मिली अभूतपूर्व प्रतिक्रिया के बाद लुधियाना का यह सेशन उद्योग जगत के लिए एक और सुअवसर बनने जा रहा है जिसमें देश के हृदय स्थल मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं से परिचित होंगे ।मध्यप्रदेश विकल्प ही नहीं बल्कि प्राथमिक निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की यह यात्रा उद्योग जगत को यह विश्वास दिलाएगी कि निवेश केवल समझौते तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नीति, प्रक्रिया और प्रदर्शन तीनों स्तर पर मध्यप्रदेश पूरी तैयारी के साथ भागीदार बनेगा।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 4 जुलाई को करेगा जनसुनवाई

भोपाल। प्रदेश की पिछड़े वर्ग की जातियों को केन्द्र की सूची में शामिल करने के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 4 जुलाई 2025 को भोपाल में जन सुनवाई करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री हंसराज गंगाराम अहीर और आयोग के सदस्य श्री भूवन भूषण कमल जनसुनवाई करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसुनवाई राज्य अतिथि गृह (व्हीआईपी गेस्ट हाउस) लालघाटी में 4 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से प्रारंभ होगी। इसमें मध्यप्रदेश की पिछड़े वर्ग की 32 जातियों (जो राज्य पिछड़ावर्ग की सूची में है, किन्तु केन्द्र की सूची में नहीं हैं।) को केन्द्र की सूची में शामिल करने पर सुनवाई करेंगे।

शहडोल सांसद ने अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

शहडोल सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह ने अपनी बेटी गिरीश नंदिनी सिंह का एडमिशन अनूपपुर जिले के ग्राम राजेंद्र के शासकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय में कराया है। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह के इस निर्णय की सराहना की। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इस सकारात्मक संदेश से अन्य जन-प्रतिनिधियों एवं नागरिकों को प्रेरणा मिलेगी। जन-सामान्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति उनका विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों की नगदी रहित उपचार स्कीम

भोपाल। देश में सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी सम्पूर्ण देश में नियमित मॉनीटरिंग कर रही है। समय-समय पर यह कमेटी विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त कर सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न योजनाओं एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जारी गाइड-लाइन्स की समीक्षा कर सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। परिवहन सचिव श्री मनीष सिंह ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिये नगदी रहित उपचार योजना के क्रियान्वयन के लिये कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी किये हैं। निर्देशों में बताया गया है कि यह स्कीम और गाइड-लाइन्स मई-2025 और जून-2025 में जारी हुई हैं। इसी के साथ मंत्रालय द्वारा 21 मई, 2025 को यूजर मैनेजमेंट पोर्टल भी जारी किया गया है।

वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर विकसित होगा 'फॉरेस्ट सफारी-जू कम रेस्क्यू सेंटर' और ठाकुरताल पर्यटन हब

जबलपुर बनेगा पर्यटन का नया केन्द्रः मंत्री सिंह

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के अनुरूप वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर मध्यप्रदेश का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर जबलपुर अब पर्यटन के क्षेत्र में भी नई पहचान की ओर अग्रसर है। पर्यटन को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के उद्देश्य से मदन महल की पहाड़ियों पर स्थित ठाकुरताल क्षेत्र को एक एमिनेंट पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस महत्वाकांयोजना में 'फॉरेस्ट सफारी - जू कम रेस्क्यू सेंटर' और संग्राम-सागर तालाब के समग्र विकास को भी सम्मिलित किया गया है। इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने वन मंडल अधिकारी ऋषि मिश्रा एवं कंसलटेंट दुबे के साथ विस्तृत चर्चा कर योजना की रूपरेखा तैयार की।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया परियोजना को और अधिक गरिमा प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे वीरांगना रानी दुर्गावती जी के नाम पर विकसित करने की घोषणा की है। यह निर्णय जबलपुर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव को और भी सशक्त करेगा। लोक निर्माण मंत्री सिंह ने इस उपलब्धि के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार भी व्यक्त किया है।

मंत्री सिंह ने बताया यह पर्यटन परियोजना लगभग 85 से 100 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जाएगी जिसमें पर्यटकों को प्राकृतिक वन्य जीवन और आधुनिक तकनीकों का समन्वित अनुभव मिलेगा। इस केंद्र में रोबोटिक इंटरप्रिटेशन सेंटर, बटरफ्लाई पार्क, तथा लॉन्ग कार्निवल जैसी आधुनिक सुविधाएँ शामिल होंगी, जिसमें येलो टाइगर, व्हाइट टाइगर, पैंथर, लायन और भालू जैसे आकर्षक वन्य-जीव रहेंगे। इसके अतिरिक्त रेप्टाइल हाउस में मगरमच्छ और सांप और एग्जॉटिक और नेटिव बर्ड्स के लिए विशेष क्षेत्र बनाए जाएंगे। ज़ेब्रा और जिराफ के लिए एक अलग एग्जॉटिक पार्क, वाटर इंटरप्रिटेशन सेंटर, और स्पीशीज वाइज इंटरप्रिटेशन सेंटर जैसे अनेक नवाचार इस परियोजना की विशेषता होगी।

मंत्री सिंह ने बताया कि पर्यटकों को रोमांच का अनुभव देने के लिए इस पूरे क्षेत्र को संग्राम-सागर तालाब से ठाकुरताल तक ट्रैकिंग, ज़िपलाइन और बोटिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे यह एक सम्पूर्ण एडवेंचर और ईको-टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सके। ठाकुरताल क्षेत्र में फॉरेस्ट बाथिंग और व्यू प्वाइंट्स जैसे प्राकृतिक आनंद देने वाले स्थल भी विकसित किए जाएंगे। मंत्री सिंह ने कहा इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अगले तीन माह में तैयार कर ली जाएगी, जिसके बाद विकास कार्यों की शुरुआत की जाएगी। यह परियोजना न केवल जबलपुर को पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाएगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर, पर्यावरण संरक्षण, और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में भी मील का पत्थर

नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृति योजना पर 3 जुलाई को एक दिवसीय कार्यशाला

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल। प्रदेश में राष्ट्रीय मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा गुरुवार 3 जुलाई को राजधानी भोपाल के होटल अशोका लेक व्यू में किया जा रहा है। इस कार्यशाला में केन्द्र सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली के वरिष्ठ सलाहकार श्री राघवेन्द्र खरे प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करेंगे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के तहत शासकीय, अनुदान प्राप्त या नगरीय निकाय के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 8वीं में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली पात्र विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष रुपये 12 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विद्यार्थी को छात्रवृत्ति के लिये आयोजित होने वाली चयन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। उक्त छात्रवृत्ति के तहत चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिवर्ष छात्रवृति की राशि प्राप्त होती है। इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर पंजीयन किया जाता है। पंजीयन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के चलते विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रह जाए इसी उद्देश्य के दृष्टिगत और योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रदेश में मातृ भाषा को दिया जाये बढ़ावा

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा में मातृ-भाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप श्रेष्ठ कार्य किया जा रहा है। श्री प्रधान ने यह बात बुधवार को भोपाल में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह से सौजन्य मुलाकात के दौरान कही। स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में 4473 शासकीय स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इन शालाओं में करीब एक लाख बच्चे नामांकित है। प्रदेश में ड्रॉप-आउट बच्चों की संख्या दर कम करने के लिए स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बारे में भी जानकारी दी।

पैरा खिलाड़ी सुश्री तिवारी की राह हुई आसान

स्पोर्ट व्हीलचेयर से खेलों में कर सकेंगी श्रेष्ठ प्रदर्शन

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

पैरा एथलीट सुश्री मनस्विता तिवारी अब और भी अच्छा प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकेंगी। उज्जैन कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के निर्देश पर एवं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा पैरा खिलाड़ी सुश्री मनस्विता तिवारी को मंगलवार को जनसुनवाई में स्पोर्ट्स व्हीलचेयर प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि सुश्री तिवारी पैरा एथलीट हैं और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।

मनस्विता तिवारी की माता श्रीमती कल्पना तिवारी ने बताया कि मनस्विता पैरा स्विमिंग, पैरा कैनोइंग, ताइक्कांडो खिलाड़ी है। मनस्विता ने पैरा स्विमिंग व पैरा कैनोइंग में राष्ट्रीय खेलों में 17 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल तथा 3 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। वही ताइक्कांडो में 01 स्वर्ण पदक व 1 रजत पदक प्राप्त किया है। मनस्विता की बचपन से ही खेलों में विशेष रुचि रही है। वह दिव्यांग है लेकिन अपनी इस कमी को ही अपनी ताकत बनाकर वह क्षेत्र व देश का नाम रोशन कर रही है। मनस्विता को अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये स्पोर्ट्स व्हीलचेयर की बहुत आवश्यकता थी, उनकी माता इसे उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं थीं।

उन्होंने जन सुनवाई में कलेक्टर उज्जैन से बात की कि शासन द्वारा यदि बेटी को व्हीलचेयर मिल सके तो वह और अधिक श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकेगी। कलेक्टर ने सुश्री मनस्विता को स्पोर्ट्स व्हीलचेयर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए। सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जयती सिंह द्वारा मनस्विता को व्हीलचेयर उपलब्ध करवाई गई। मनस्विता की माता श्रीमती कल्पना तिवारी ने इस अप्रतिम सहयोग के लिए राज्य शासन का आभार व्यक्त किया है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्यप्रदेश को फ्रंट रनर स्टेट का दर्जा

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

सतत विकास के लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित करने में मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसी क्रम में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन में निजी उद्योग की भूमिका और सहभागिता को बढ़ाने के लिए भारत जर्मन सहयोग परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा विशेषज्ञों की राष्ट्रीय कार्यशाला भोपाल के कोर्टयार्ड बाय मैरियट भोपाल में 3 जुलाई को सुबह दस बजे से आयोजित की गई है।

कार्यशाला में मध्यप्रदेश के विभिन्न विभाग, जिलों के प्रतिनिधियों, नीति आयोग, जर्मनी की संस्था जीआईजेड के प्रतिनिधियों से सतत विकास के लक्ष्यों और उनके स्थानीयकरण के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मध्यप्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण में तेजी आई है और एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्यप्रदेश को फ्रंट रनर स्टेट का दर्जा मिला। प्रदेश में उत्पादन और जिम्मेदार पूर्ण उपभोग, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ स्वच्छता, शहरीकरण, गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय काम हुआ है। मध्यप्रदेश के प्रयासों से 2.30 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं।

सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करते हुए मध्यप्रदेश में खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा हासिल करने के लिए आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत के प्रावधान के लिए जल जीवन मिशन में उल्लेखनीय काम हुआ है। मध्यप्रदेश देश के उन पहले राज्यों में से एक है जिसने भोपाल शहर के लिए स्वच्छिक स्थानीय समीक्षा की और इंदौर नगर निगम में ग्रीन म्युनिसिपल बांड के माध्यम से वित्त जुटाने में अग्रणी भूमिका निभाई।